



राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग

प्रलिस के लयि:

NCST, ST से संबंघति संवैधानकि प्रावधान ।

मेन्स के लयि:

NCST: कार्य, अनुसूचति जनजात: प्रावधान, पहल ।

चर्चा में क्यों?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) द्वारा प्रदान कयि गए नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग \(National Commission for Scheduled Tribes- NCST\)](#) वर्तमान में अधिकृत सदस्यों की संख्या के आधे से भी कम के साथ कार्यरत है ।

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग:

- गठन: NCST की स्थापना वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन कर और 89वें संवधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से [संवधान में एक नया अनुच्छेद 338A](#) सम्मलित कर की गई थी, इसलिये यह एक संवैधानकि नकिय है ।
 - इस संशोधन द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात आयोग को दो नमिनलखिति अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतस्थापित कयि गया था:
 - [राष्ट्रीय अनुसूचति जात आयोग \(NCSC\)](#), और
 - [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग](#)
- उद्देश्य: NCST को संवधान के अनुच्छेद 338A के तहत वर्तमान में प्रभावी कसि कानून या सरकार के कसि अन्य आदेश के अंतर्गत [अनुसूचति जनजातियों \(ST\)](#) को प्रदान कयि गए वभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की नगिरानी का अधिकार दयिा गया है । **NCST यह आकलन करने के लयि भी अधिकृत है कयि सुरक्षा उपाय कतिनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं ।**
- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जनिहें [राष्ट्रपति](#) अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत अधपित् द्वारा नयिक्त करेगा ।
 - इसमें एक महिला सदस्य का होना अनवार्य है ।
 - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लयि पद धारण करते हैं ।
 - अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के दर्जे के समकक्ष माना गया है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और अन्य सदस्य भारत सरकार के सचिवि दर्जे के होते हैं ।
 - सदस्य दो से अधिक कार्यकाल हेतु नयिक्त के लयि पात्र नहीं हैं ।

NCST के कर्तव्य और कार्य:

- संवधान या कसि अन्य कानून या सरकार के कसि आदेश के अधीन [अनुसूचति जनजातियों के लयि प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंघति सभी मामलों की जाँच एवं नगिरानी करना ।](#)
- अनुसूचति जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंघ में [वशिष्ट शकियतों की जाँच करना ।](#)
- [अनुसूचति जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रयिा में भाग लेना और सलाह देना](#) तथा उनके विकास की प्रगतिका मूल्यांकन करना ।
- [आयोग सुरक्षा उपायों के संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतविर्ष और आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्रदान करेगा ।](#)
- इन रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संघ या कसि राज्य द्वारा कयि जाने वाले [उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सफारशें करना ।](#)
- राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई कसि वधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नयिम द्वारा [अनुसूचति जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंघति कसि अन्य कृत्य का नरिवहन कर सकेगा ।](#)

भारत में अनुसूचति जनजातियों से संबंधति प्रावधान:

परभाषा:

- भारत का संवधान अनुसूचति जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परभाषति नहीं करता है। वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचति जनजातियों को "बहष्कृत" और "आंशकि रूप से बहष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पछिड़ी जनजातियों" के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 1935 के भारत सरकार अधनियम ने पहली बार प्रांतीय वधानसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतनिधियों का आह्वान कया।

संवधानकि प्रावधान:

- अनुच्छेद 366(25):** यह केवल अनुसूचति जनजातियों को परभाषति करने हेतु प्रकरया नरिधारति करता है:
 - इसमें अनुसूचति जनजातियों को "ऐसी आदवासी जातया आदवासी समुदाय या इन आदवासी जातियों और आदवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में परभाषति कया गया है, जनिहें इस संवधान के उद्देश्यों के लयि अनुच्छेद 342 में अनुसूचति जनजातियाँ माना गया है"।
- अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति, कसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधसूचना दवारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या उनके समूहों को वनरिदषिट कर सकेगा।
- पाँचवीं अनुसूची:** यह छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों और अनुसूचति जनजातके प्रशासन एवं नयित्रण हेतु प्रावधान नरिधारति करती है।
- छठी अनुसूची:** यह असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधति है।

वैधानकि प्रावधान:

- अस्पृश्यता के वरिद्ध नागरकि अधिकार संरक्षण अधनियम, 1955
- अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अतयाचार नवारण) अधनियम, 1989**
- पंचायत उपबंध (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधनियम (पेसा), 1996**
- अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरकि वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006**

नष्करष

आयोग में रक्तियों को तुरंत भरा जाना चाहयि अरथात् इसमें देरी करने का कोई कारण नहीं है क्योकभरती नयिमों को उपयुक्त रूप से संशोधति कया गया है। इसके अलावा जनशकतकी कमी कार्यों के संचालन में भी कठनाइयों का कारण बन रही है, जससे आयोग के प्रभावी प्रदर्शन हेतु रक्तियों को तुरंत भरना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. प्रत्येक वर्ष कतपयि वशिषिट समुदाय/जनजात, पारस्थितिकि रूप से महत्त्वपूर्ण, मास-भर चलने वाले अभयान/त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों का पौधरोपण करते हैं। नमिनलखिति में से कौन-से ऐसे समुदाय/जनजात हैं? (2014)

- भूटया और लेपचा
- गोंड और कोरकू
- इरूला और तोडा
- सहरया और अगरया

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संवधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में कसिसे संबंधति प्रावधान हैं? (2015)

- अनुसूचति जनजातियों के हतियों की रक्षा
- राज्यों के बीच सीमाओं का नरिधारण
- पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़मिमेदारियों का नरिधारण
- सभी सीमावर्ती राज्यों के हतियों की रक्षा

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संवधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लयि नजी पारटियों को आदवासी भूमिके हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषति कया जा सकता है? (2019)

(A) तीसरी अनुसूची

- (B) पाँचवी अनुसूची
(C) नौवी अनुसूची
(D) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

प्रश्न. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022)

- (a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।
(b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।
(c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा।
(d) ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या हैं? (मुख्य परीक्षा- 2017)

स्रोत: द द्रिस्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-commission-for-scheduled-tribes-1>

